

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से

पाकिस्तान ने मध्य-दक्षिणी एयरस्पेस 2 दिन के लिए बंद किया...इसे भारत के सैन्य अभ्यास 'त्रिशूल' से जोड़ा जा रहा...

नई दिल्ली,25 अक्टूबर 2025। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अभ्यास 'त्रिशूल' के पहले मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्र को 28 और 29 अक्टूबर को बंद करने का फैसला किया। शनिवार को जारी नोटिस टू एयरमैन के अनुसार,दो दिन हवाई मार्ग उपलब्ध नहीं रहेंगे और उड़ानों पर रोक रहेगी। हालांकि,पाकिस्तान ने इस कदम के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी सैन्य अभ्यास या हथियार परीक्षण से जुड़ा हो सकता है। वहीं, जानकार इसे सैन्य अभ्यास 'त्रिशूल' से जोड़कर देख रहे हैं। यह अभ्यास सर क्रीक के पास,यानी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में होगा। रक्षा विश्लेषक डेमियन सायमोन ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि इस अभ्यास का दायरा 28 हजार फीट ऊंचाई तक फैला होगा। जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है।

पाकिस्तान बॉर्डर पर जुटेंगे 30 हजार सैनिक
राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिन अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी,एयरफोर्स और नौसेना के 30 हजार जवान थार में जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी,जो 10 नवंबर तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर कुछ एरिया में कॉमर्शियल फ्लाइट्स के रूट में बदलाव भी हो सकता है। एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सर क्रीक इलाके तक होगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के दौरान सर क्रीक सीमा विवाद की चर्चा की थी इसके जरिए पश्चिमी एयर कॉरिडोर में उड़ानों के लिए चेतावनी दी गई है। इस दौरान कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए इस एरिया के रूट में बदलाव हो सकता है।

ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद सतर्कता बढ़ी,ड्रोन हमलों पर फोकस
हाल ही में पश्चिमी सीमा पर हुए ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज में विशेष रूप से काउंटर-ड्रोन सिस्टम,संचार बाधा (जैमिंग) और ऑटोमैटिक सेक्वेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी मॉडर्न तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना प्रिसिशन स्ट्राइक,एयर डिफेंस इंटरसेप्शन और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस पर विशेष ध्यान देगी।

तीनों सेनाएं नई तकनीक और युद्ध प्रणाली परखेंगी
तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित कर यूनिफाइड ऑपरेशन,डीप स्ट्राइक और मल्टी-डोमेन ऑरफेयर का अभ्यास करेंगी। इस दौरान भारतीय सेना अपने कई नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टमों की टेस्टिंग भी करेगी। इनमें टी-90 एस और अर्जुन टैंक,हॉवित्जर तोर्पें,अपारचे अटैक हेलिकॉप्टर,हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर शामिल होंगे। यह अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ तक होगा। कच्छ का इलाका समुद्र के पास है, इसलिए वायुसेना और नौवी के विशेष विमान इस इलाके में मिलकर काम करेंगी। अभ्यास के दौरान ड्रोन,सटीक-निर्देशित मिसाइलें,लॉन्जर रेंज मिस्सिल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। यह अभ्यास दक्षिण-पश्चिमी वायुसेना कमान की रेंजिंस और क्राइडोनेशन को परखने का भी बड़ा मंच बनेगा।

चीन सीमा विवाद के बीच रणनीतिक संदेश
यह अभ्यास सिर्फ पश्चिमी मोर्चे तक सीमित नहीं है,बल्कि इसका रणनीतिक संदेश पूर्वी सीमा की ओर भी है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत यह दिखाना चाहता है कि वह दोनों मोर्चों पर एकसाथ संचालन करने में सक्षम है। 'महागुजराज' इस दृष्टि से रणनीतिक गहराई और परिचालन तत्परता को सशक्त करने वाला अभ्यास माना जा रहा है। अभ्यास के दौरान यूएवी (ड्रोन),सटीक-निर्देशित मिसाइलें,लॉन्जर रेंज मिस्सिल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। यह अभ्यास दक्षिण-पश्चिमी वायुसेना कमान की रेंजिंस और क्राइडोनेशन को परखने का भी बड़ा मंच बनेगा।

ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद अभ्यास का बड़ा महत्व
पश्चिमी सीमा पर हाल ही में हुए ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों और घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि देखी गई थी। इसी पृष्ठभूमि में 'महागुजराज' अभ्यास का महत्व और बढ़ गया है। इसमें काउंटर-ड्रोन सिस्टम,संचार बाधा (जैमिंग) और ऑटोमैटिक सेक्वेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं है,बल्कि तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता को वास्तविक परिस्थितियों में परखना भी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और संचार बाधा तकनीक को भी परखा जाएगा। साथ ही, यह अभ्यास नवीनतम युद्ध प्रौद्योगिकियों जैसे मानव रहित हवाई वाहन,सटीक निर्देशित मिसाइल और लॉन्जर रेंज मिस्सिल की क्षमताओं का परीक्षण भी करेगा।

महिला डॉक्टर सुसाइड केस में सांसद का आ रहा नाम

महाराष्ट्र,25 अक्टूबर 2025। सतारा जिले में गुरुवार को एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले अपने हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने दो पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं, इसी बीच सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर को लेकर एक जानकारी सामने आई है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सतारा पुलिस किसी आरोपी को पकड़ के रात को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाती थी। ऐसे में उस समय अगर सुसाइड करने वाली डॉक्टर ड्यूटी पर रहती थी तो वह उन आरोपियों को अनफिट डिकलेयर करके एडमिट कर लेती थी। इसके पीछे की वजह यह थी की रात में आरोपियों को लाने से सस्का काम बढ़ता था। साथ ही अपना काम कम करने के लिए वह उन्हें फिट होने के बावजूद अनफिट करार देकर एडमिट कर लेती थी। ऐसा तीन से चार बार होने के बाद पुलिस ने जिला मेडिकल काउंसिल को शिकायत भी की थी। वहीं, इस पर जब मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर से जवाब मांगा तो उसने जो जवाब दिया वह हैरान करने वाला था। डॉक्टर ने जवाब में कहा था कि एक एमपी का फोन आया था। एमपी की तरफ से उसपर दबाव भी बनाया गया। हालांकि, जवाब में डॉक्टर ने किसी भी एमपी का नाम नहीं बताया था। लेकिन यह मामला सुसाइड केस से नहीं जुड़ा था। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर को कथित आत्महत्या की स्वतंत्र जांच और विशेष जांच दल से जांच के लिए सभी पार्टी के नेताओं ने मांग की है। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडाने ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया,जबकि साफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बीयर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

देश को मिलने वाले हैं नए चीफ जस्टिस
नई दिल्ली,25 अक्टूबर 2025। जस्टिस बीआर गवई के 23 नवंबर को रिटायर होने के बाद भारत को नया चीफ जस्टिस मिलेगा। सरकार ने इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी के नाम के लिए अनुरोध पत्र जल्द ही सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत इस कतार में अगले हैं। उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा वर्तमान चीफ जस्टिस से प्राप्त की जाएगी और इसके बाद राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने तक रहेगा,यानी 9 फरवरी 2027 तक। यह कार्यकाल भारत के न्यायिक इतिहास में मुख्य न्यायाधीश के लिए औसतन मानक कार्यकाल के अनुरूप है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक सेवा में दो दशक से अधिक अनुभव हासिल किया है और उच्चतम न्यायालय में आते ही कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई है।

महिला भिखारी के पास लाखों रुपए कैश मिले,हर कोई हैरान

कनॉटक,25 अक्टूबर 2025। मंगलौर में उस समय लोग दंग रह गए जब एक महिला भिखारी के पास से लाखों रुपए की ख़म बरामद हुई। महिला ने पैसे कुड़े में छिपाये हुए थे। फिलहाल पैसे और महिला को जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलौर के मोहल्ला पटनापुरा से एक दिव्यांग महिला भिखारी जो कि दिमागी रूप से भी कमजोर बताई गई है। वह लगभग 13 वर्षों से एक मकान के बाहर रहती थी। बीते रोज मोहल्ले के लोगों ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया तो कुड़ेदान के पास रखे कुछ कट्टे उसने अपने पास छिपा लिए। साथ ही सुबह से शाम तक महिला उन कट्टों को अपने पास चिपका कर बैठी रही।

इंजीनियर ने कार से 8 को रौंदा,5 की मौत

आगरा में डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी,फिर भागने में 4 को और मार डाला

आगरा,25 अक्टूबर 2025। आगरा में एक इंजीनियर की बेकाबू कार ने डिलीवरी बॉय समेत 8 लोगों को रौंद दिया। हदसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं,जिनमें से 2की हालत गंभीर है। हदसा शुक्रवार रात न्यू आगरा थाने से कुछ दूरी पर नगला पुरी में हुआ। हदसे वाली जगह के नजदीक पुलिस चेकिंग कर रही थी। यह देखकर कार चला रहा अंशुल घबरा गया। वहां से भागने के लिए उसने स्पीड बढ़ाकर 100 से ज्यादा कर ली। उसने पहले डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंशुल फिर भी नहीं रुका। उसने 400 मीटर के दायरे में दो जगहों



पर 7 और लोगों को रौंद दिया। इसमें 4 लोगों की जान चली गई। इसके बाद कार डिवाइडर से टक्करकर पलट गई। हदसे के बाद लोगों ने कार चालक अंशुल को पकड़ लिया और पीट दिया। भीड़ ने

का रहने वाला है। वह नोएडा में एरिक्सन कंपनी में इंजीनियर है।अंशुल शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। दिवाली की छुट्टियों में वह घर आया था। लोगों का कहना है कि अंशुल नशे में था। गनीमत रही कि कार पलटने पर एयरबैग खुल गए, जिससे उसे चोट नहीं आई। हदसे में मृतक की पहचान कमल,भानु प्रताप,कृष्,बंदेश और बबली के रूप में हुई। हदसे में बचे राहुल ने बताया कि वह सड़क किनारे मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी अचानक कार हवा में उड़ते हुए मेरे ऊपर गिरी। मैं करीब 10 मिनट तक कार के नीचे दबा रहा।

पिछले 11 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई : नड्डा

नई दिल्ली,25 अक्टूबर 2025। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. जे. पी. नड्डा ने शनिवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई है। इसी अवधि में स्नातक सीटें 51,000 से बढ़कर 1,29,000 और स्नातकोत्तर सीटें 31,000 से बढ़कर 78,000 तक पहुंच गई हैं। अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त सीटें जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में भी भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मातृ

बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनानी होगी क्योंकि महागठबंधन के पास न नेता हैं,न नीयतः अमित शाह

पटना,25 अक्टूबर 2025। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में खगड़िया के बाद मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के नौवागढ़ी में जनसभा को संबोधित किया और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने पूर्व की गैर भाजपा सरकारों पर निशाना भी साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने काफी काम किया। इसका लाभ बिहार के किसानों को भी मिला। इससे फसलों के उत्पादन में बिहार का पूरा देश में स्थान बना। इसे आगे भी कायम रखना है,तो फिर से राजग का डबल इंजन सरकार। उन्होंने कहा कि लालू तदक अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो

न नेता है और न ही नीयत। अमित शाह ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई, अस्पतालों में वक्त पर दवाई,खेतों की समय पर सिंचाई और हर घर में शुद्ध जल की सपनाई,यही लक्ष्य के साथ काम कर रही बिहार में डबल इंजन की सरकार। उन्होंने कहा कि लालू तदक अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो

चक्रवात मोन्था के चलते आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी

अमरावती,25 अक्टूबर 2025। चक्रवात मोन्था धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा है और धीरे-धीरे एक दबाव क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि यह कल तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ऐसे में तमिलनाडु,आंध्र प्रदेश,पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। आईएमडी के अनुसार इसके प्रभाव से 90-110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से हवाएं चलेंगी। यह तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। यह वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर से 420 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम,विशाखापत्तनम से 990 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम,चेन्नई से 990 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा से 1000 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर से 1040 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में है।

मणिपुरः अलग-अलग अभियानों में 4 उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल,25 अक्टूबर 2025। राज्य के तीन जिलों में एक साथ चलाए गये पुलिस अभियानों के दौरान 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार और पहचान के कागजात जब्त किए गए हैं। मणिपुर पुलिस की तरफ से शनिवार को दी गयी आधिकारिक जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर को सबसे बड़ी गिरफ्तारी चुराचांदपुर जिले में हुई, जहां पुलिस ने 18 साल के हाओमिनथांग हाओकिप को पकड़ा, जो यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) का सक्रिय सदस्य है। उसे ओल्ड गेलमौल स्थित उसके घर से पकड़ा गया। अधिकारियों को दो जिंदा राउंड से भरी पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन और आधारकार्ड मिला। अधिकारियों के मुताबिक, हाओकिप चुराचांदपुर शहर में व्यापारियों और आम लोगों से जबनर वसूली के साथ दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त था। काकचिंग जिले में पुलिस ने 23 साल के सलाम सुशोल सिंह को



गिरफ्तार किया,जिसकी पहचान प्रतिबंधित संगठन कैसीपी (ताइबंगनबा) के सक्रिय कैडर के तौर पर हुई है। यह गिरफ्तारी काकचिंग वैरी बामन परंग इलाके में उसके घर से हुई। सुरक्षाकर्मियों ने उसके पास से मोबाइल फोन, आधारकार्ड और पैन कार्ड जब्त किया। तीसरी गिरफ्तारी इंफाल वेस्ट जिले में हुई,जहां शमजेत्साबम संजीत सिंह (42), जिन्हें इनाओबी और नोंगशाबा के नाम से भी जाना जाता है,उसे पटसोई पुलिस स्टेशन के इलाके के सगेथेल माखा लेंडकाई से गिरफ्तार किया गया।

संपादकीय

तेल प्रतिबंध में अवसर

सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर चारों तरफ से जिस तरह से दबाव बनाते रहे हैं,उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। एक ही मुद्दे पर उनकी नीति चीन-पाकिस्तान व भारत को लेकर अलग-अलग होती है। उनके हालिया कदमों से भारतीय विदेश नीति असहजता के दौर से गुजर रही है। ट्रंप की भारत को मुश्किल में डालने की तमाम घोषणाएं, अब चाहे मनमाना टैरिफ थोपना हो या भारतीय प्रतिभाओं व नागरिकों पर तरह-तरह की बंदिशें लगाना हो,भारतीय जनमानस में नाराजगी का सबब बनती रही है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप ये दबाव अमेरिका की प्राथमिकताओं के साथ व्यापार समझौते पर भारत को झुकाने के लिये बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ दरियादिली को भी इसी कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। अब इसी कड़ी में रूस से आने वाला सस्ता तेल बंद करवाना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता बनी है। भारत कहता रहा है कि वह अपने 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को अपने बजट में लाने हेतु रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है,जिसका रूस-यूक्रेन युद्ध से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन भारत की संपिट विदेश नीति पर दबाव बनाने हेतु ट्रंप प्रशासन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में रूसी तेल के दो सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी कड़े प्रतिबंध भारत की जीने वाली रूसी तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। संभव है कि भारत के कूट औपत्य खरीदने के विकल्प इन प्रतिबंधों से सीमित हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि यह कदम अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते में एक बड़ी बाधा दूर करने वाला कारक भी साबित हो सकता है। कुछ जानकार राष्ट्रपति ट्रंप की यह घोषणा,रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिये रुकी हुई वार्ताओं को लेकर बड़ती निराशा से उभजी बता रहे हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद,भारत रियायती रूसी कच्चे तेल का दूसरा बड़ा खरीददार रहा है। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन प्रशासन का आरोप रहा है कि तेल कंपनियां क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करने में मदद कर रही हैं। ट्रंप और उनके टीम के सदस्य कई बार भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के बेतुके आरोप भी लगाते रहे हैं। जिसके चलते ट्रंप प्रशासन ने रूसी कच्चे तेल का आयात करने पर प्रतिशोध के चलते भारत से आने वाले सामानों पर 25 फीसदी का दंडात्मक शुल्क भी लगाया था। भारत सरकार के लिये यह श्रेय की बात है कि वह रूसी तेल खरीद रोकने के दबाव का दृढ़ता से विरोध करती रही है। भारत सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। निःसंदेह,भारत को अब एक और कठिन संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौजूदा चुनौतियों के बीच यदि एक सुनियोजित पुनर्निर्माण का आवश्यकता है, तो ऐसा करना चाहिए। वैसे भारी दबाव के बाद भी मोदी सरकार ने ट्रंप सरकार के बार-बार दिए गए उस बयान से खुद को अलग कर लिया है कि वह रूसी तेल आयात में भारी कमी लाएगी। लेकिन अब नये प्रतिबंधों का पालन करने के लिये भारतीय रिफाइनरियों के लिये अल्पावधि में रूसी तेल सौदों से पीछे हटना निश्चित प्रतीत होने लगा है। आने वाले समय में यह दबाव कितना रहेगा,यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप,दोनों इस नवीनतम टकराव को किस हद तक झेलने के लिये तैयार हैं। भारतीय रिफाइनरियां आवश्यकता पड़ने पर आसानी से नये स्रोतों की ओर रुख कर सकती हैं और अमेरिकी टैरिफ में कमी करके महंगे तेल आयात की भरपाई की जा सकती है। भारत के हितों के अनुकूल निर्णय लेने की अपनी स्वातन्त्रता पर जोर देना, नई दिल्ली के लिये असली चुनौती है। हमने सस्ता रूसी तेल खरीदने में एक अलग राह चुनी। अब समय आ गया है कि प्रतिबंधों का लाभ उठाकर अमेरिका के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता किया जाए,जो दोनों देशों के लिये फायदेमंद हो।

कायस्थ राजवंशो का ऐतिहासिक गौरव

विवेक दत्तजगन्नीकलात

भारतीय समाज में हमेशा कायस्थ समुदाय का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परंपरागत रूप से लेखन, प्रशासन और राजकीय कार्यों से जुड़े इस समुदाय ने न केवल प्रशासकों और मंत्रियों के रूप में बल्कि स्वतंत्र शासकों और राजवंशों के रूप में भी भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजा टोडरमल अकबर के प्रमुख दरबारी थे। कायस्थ राजवंशों के ऐतिहासिक योगदान,उनके शासन क्षेत्रों और वर्तमान परिदृश्य में उनकी स्थिति का विश्लेषण इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कायस्थ समुदाय की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार,कायस्थ चित्रगुप्त के वंशज माने जाते हैं। पद्य पुराण में उल्लेख है कि चित्रगुप्त जी के दो विवाह हुए और उनके कुल बारह पुत्र हुए,जिनसे कायस्थों की विभिन्न उपशाखाएं विकसित हुईं। इतिहासकारों के अनुसार,गुप्त काल से पूर्व ही बंगाल में कायस्थ पद की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल में कायस्थ समुदाय का इतिहास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मुस्लिम विजय के परचात,बंगाली कायस्थों ने क्षेत्र के पुराने हिंदू शासक वंशों सेन,पाल,चंद्र और वर्मन राजवंशों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार वे बंगाल के सरोगेट शासक योद्धा बन गए। बंगाली कायस्थ कई कुलों में विभाजित थे,जिनमें कुलीन कायस्थ उच्च श्रेणी के थे। पारंपरिक कथाओं के अनुसार,बोस,घोष,मित्रा, गुहा और दत्ता पांच प्रमुख बंगाली कायस्थ उप जातियां थे। गौड़ कायस्थों में नंदी,पाल,इंद्र,कर,भद्र,भर,ऐच,सुर,दाम,बर्धन,शील,चाकी और आध्य जैसे प्रमुख कुल शामिल थे।

ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख है कि गौड़ कायस्थों में महाभारत काल के भागदत्त और कलिंग के रुद्रदत्त जैसे राजा हुए थे। मध्यकाल में बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में कायस्थ परिवारों ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परिवारों ने न केवल राजनीतिक सत्ता का प्रयोग किया बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को भी समृद्ध किया। बंगाली कायस्थों का योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था,बल्कि वे साहित्य,कला और शिक्षा के क्षेत्र में भी सदैव अग्रणी बने रहे। दक्षिण भारत में,विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में,कायस्थ राजवंश ने तेरहवीं शताब्दी में शासन किया। यद्यपि ये नाममात्र रूप से काकतीय राजवंश के अधीन थे,किंतु व्यावहारिक रूप से वे स्वतंत्र शासक थे। कायस्थ राजवंश ने आंध्र में पनपुलग से मार्जवाड़ी तक विशाल क्षेत्र पर शासन किया,जिसकी राजधानियां वल्लूर और गांडिकोट्टा थीं। इस राजवंश में चार शासक हुए,जो सभी महान योद्धा और प्रशासक के रूप में विख्यात थे। गांडिकोट्टा का किला आज भी उनकी स्थापत्य कला और सैन्य दक्षता का प्रमाण है। यह किला अपनी सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था और कायस्थ राजाओं की सैन्य कुशलता को प्रदर्शित करता है। उत्तर भारत में चित्रगुप्तवंशी कायस्थों की विभिन्न शाखाएं थीं जिनमें अभिष्ट,भारता,बाल्मीकि,भट्टनागर इत्यादि थीं। ग्यारहवीं शताब्दी के बाद के शिलालेखों में विभिन्न क्षेत्रीय वंशों का उल्लेख मिलता है जो उत्तर भारतीय कायस्थों की शाखाओं से संबंधित थे। इन वंशों को उनकी सामान्य व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ पहचाना जाता था और जिनके सदस्य मध्यकालीन राज्यों के प्रशासन में विशेष रूप से प्रभावशाली हो गए थे। कुछ कायस्थों ने सैन्य कमांडों और क्षेत्रीय सरकारों के रूप में भी पद संभाले।

नियंत्रण या निगरानी:असम के नए कानूनों का व्यापक संदेश



डॉ. प्रियंका सौरभ

कानून ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता,धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे सामाजिक सुधार मानते हैं,जबकि आलोचक इसे राज्य द्वारा निजी जीवन में हस्तक्षेप बताते हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के वास्तविक उपाय शिक्षा,स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से आते हैं,न कि कटोर कानूनों से। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिकों को नियंत्रित नहीं,बल्कि सक्षम बनाया जाए। भारत जैसे विविध और बहुधार्मिक देश में जब कोई राज्य व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषयों पर नीति बनाता है,तो उसका असर सीमित नहीं रहता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा प्रस्तावित विवाह और जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी तरह की राष्ट्रीय बहस को जन्म दे रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक संतुलन और अवैध प्रजनन वृद्धि पर रोक लगाने की दिशा में है,जबकि आलोचकों का मानना ​​है कि यह नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। यही विरोधाभास आज की राजनीति और समाज की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। असम लंबे समय से प्रवासन,जनसंख्या असमानता और सांंप्रदायिक तनाव के मुद्दों से जूझता रहा है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहाँ बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों की समस्या पर राजनीति हमेशा सशक्त रही है। इस पृष्ठभूमि में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री सरमा का कहना है कि राज्य में कुछ समुदायों में जनसंख्या

वृद्धि दर बहुत अधिक है,जिससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। उनके अनुसार,यदि राज्य में शैक्षिक और आर्थिक समानता लानी है,तो ऐसे कटोर कदम आवश्यक हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ही सबसे उपयुक्त उपाय है? भारत में पहले भी ऐसे प्रयास किए गए हैं...इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी अभियान इसका उदाहरण है। उस अनुभव ने दिखाया कि जनसंख्या नियंत्रण केवल कानून या दंड से नहीं,बल्कि शिक्षा,स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से हासिल किया जा सकता है। असम का प्रस्तावित कानून अगर विवाह आयु,बहुपतित्व या धर्मांतरण जैसे निजी विषयों को नियंत्रित करने की दिशा में जाता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान नागरिक अधिकारों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करेगा। संविधान नागरिकों को अपने धर्म और जीवनशैली की स्वतंत्रता देता है। विवाह और परिवार व्यक्ति की निजता का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' इन विषयों को भी सम्मिलित करता है। यदि कोई सरकार यह तय करने लगे कि कौन किससे और कैसे विवाह करे या कितने बच्चे हों,तो यह राज्य और व्यक्ति के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। यही कारण है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे एक निगरानीवादी नीति कह रहे हैं,न कि सुधारवादी कदम।

भारत में समान नागरिक संहिता पर पहले से बहस जारी है। असम का यह कानून उस बहस को और तीव्र कर सकता है। सरकार का तर्क यह हो सकता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम होना चाहिए,चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। परंतु इस समानता की अवधारणा तभी सार्थक है जब यह स्वेच्छिक और परामर्श आधारित हो,न कि भय और नियंत्रण पर आधारित। यदि किसी एक समुदाय को लक्ष्य बनाकर नीति बनाई जाती है,तो वह सुधार के बजाय विभाजन का कारण बनती है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो जनसंख्या वृद्धि केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं होती। यह शिक्षा की कमी,गरीबी,स्वास्थ्य सुविधाओं की अपुलब्धता और लैंगिक असमानता से अधिक प्रभावित होती है। जब तक महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी

जाएगी,तब तक परिवार नियोजन के कानून केवल कागजों पर रह जाएंगे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण का जो उदाहरण पेश किया है,वह शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश का परिणाम है,न कि किसी कटोर कानून का। असम जैसे राज्य में जहाँ साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है, वहाँ नए कानूनों के बजाय सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता अधिक है। यदि सरकार उन क्षेत्रों में निवेश करे जहाँ महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ पिछड़ी हुई हैं,तो जनसंख्या वृद्धि स्वतः नियंत्रित हो सकती है। इसके विपरीत,यदि सरकार नियंत्रण के नाम पर कटोराट दिखाती है,तो यह अविश्वास और भय का वातावरण बना सकती है। राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के लिए अवसर लेकर आया है। सत्तापक्ष इसे सुधार की दिशा में साहसिक कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक धुंधीकरण का प्रयास मान रहा है। असम में चुनावी सभिकरण हमेशा से जातीय और धार्मिक पहचान पर आधारित रहे हैं। इसलिए यह नीति किसी एक वर्ग को साधने और दूसरे को असुरक्षित महसूस कराने का साधन बन सकती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है। मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इस विषय को लव जिहाद,बहुपतित्व और जनसंख्या विस्फोट जैसे विवादास्पद शब्दों से जोड़ा जा रहा है। परंतु यह समझना आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक नीति का विषय है। यदि इसे धर्म के चरम से देखा जाएगा, तो समस्या सुलझने के बजाय और गहरी हो जाएगी। असम सरकार का यह दावा है कि एक कानून का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है,बल्कि समाज में संतुलन स्थापित करना है।

परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसे कानूनों के लागू होने के तरीके में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रशासनिक स्तर पर यह तय किया जाए कि किसे बहुपतित्व या अवैध विवाह के तहत दंडित किया जाए,तो यह निर्णय अधिकारी की व्यक्तिगत धारणा पर भी निर्भर करेगा। यही वह बिंदु है जहाँ लोकतांत्रिक शासन को पारदर्शिता और जवाबदेही की सबसे अधिक आवश्यकता



होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कानूनों का क्रियान्वयन। भारत में पहले से ही कई जनकल्याणकारी कानून बने हैं,पर उनका प्रभाव सीमित रहा है क्योंकि उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रही है। यदि असम सरकार नया कानून बनाती है लेकिन उसका कार्यान्वयन पक्षपाती या छीला रहता है,तो यह सिर्फ दिखावे का कदम रह जाएगा। इसलिए, किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके उद्देश्य से अधिक,उसके कार्यान्वयन से किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब किसी राज्य में नागरिकों को यह महसूस होता है कि सरकार उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है,तो नागरिक और राज्य के बीच विश्वास की दीवार कमजोर होती है। लोकतंत्र का आधार वही विश्वास है। भारत की राजनीति पहले से ही विश्वास संकट से गुजर रही है...संस्थाओं पर भरोसा घट रहा है,संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ने ले ली है। ऐसे में यदि नीतियाँ लोगों को और बाँटने लगें,तो लोकतांत्रिक समाज में अस्थिरता बढ़ना स्वाभाविक है। इस विषय का वैश्विक संदर्भ भी दिलचस्प है। चीन ने दशकों तक एक कच्चे की नीति अपनाई थी,जिसके दुष्परिणाम अब समने हैं वृद्ध आबादी बढ़ी,कार्यबल घटा,और लैंगिक असंतुलन पैदा हुआ। बाद में चीन को अपनी नीति पलटनी पड़ी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण यदि कटोर रूप से लागू किया जाए,तो वह नागरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में तो ऐसा कदम और भी

संवेदनशील है क्योंकि यहाँ विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें नियंत्रण नहीं,बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में सोचें। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगार और समान अवसर से छोटे-यह बहस केवल असम तक नहीं,बल्कि सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हैं। यह परिवर्तन कानून से नहीं,चेतना से आता है। असम के इस प्रस्ताव को यदि वास्तव में सुधारवादी बनाया है,तो उसे राजनीतिक नारों से हटाकर व्यावहारिक योजनाओं से जोड़ना होगा। जनसंख्या नीति का लक्ष्य केवल संख्या घटाना नहीं होना चाहिए,बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए। राज्य को यह समझना होगा कि अनुशासन कानून से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है। अंततः यह बहस केवल असम तक सीमित नहीं रहेगी। यह उस रास्ते का संकेत है जिस पर भारत आगे बढ़ सकता है या तो नियंत्रण के राज्य की ओर,जहाँ सरकारें नागरिकों के जीवन के हर पहलू को निर्धारित करेंगी,या फिर जागरूकता आधारित समाज की ओर,जहाँ नागरिक स्वयं अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होंगे। लोकतंत्र का अर्थ तभी पूरा होता है जब राज्य मार्गदर्शक बने,मालिक नहीं। असम की पहल शायद ईमानदार चिंता से उत्पन्न हो,पर इसका रूप और परिणाम सावधानी से तय किया जाना चाहिए। एक संवेदनशील लोकतंत्र में हर नीति का मूल्यांकन उसके प्रभाव से होना चाहिए,न कि उसके नारे से।

परीक्षा में नवाचार के समांतर चुनौतियां

परीक्षा के मानकों और जटिलताओं के मस्ते पर पिछले लंबे समय से बहस होती रही है। इसमें यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या हमारी मौजूदा परीक्षा प्रणाली किसी विद्यार्थी के भीतर की संभावनाओं और क्षमता का आकलन कर पाने में तरह सक्षम होती है। परीक्षा क्यों ली जाती है? इसका मापदंड क्या सिर्फ पढ़े हुए विषय का कठोर एकाग्र रखा,यानी खुली किताब वाली परीक्षा। उसमें एक विषय के पहले सत्र की पहली परीक्षा में छात्रों को प्रश्न देते हुए कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी किताब को खोल कर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न मुश्किल से छह रहे होंगे और उनमें से छात्रों को सिर्फ दो या तीन प्रश्न हल करने थे। छात्रों ने प्रश्न देखा और किताबें खोलने लगे। प्रश्नापक मुस्कुरा रहे थे,छात्रों को किताबों में झांके हुए देख कर छोटे शहरों से आए छात्र छात्राओं के लिए खुली किताब वाली परीक्षा देने का यह प्रथम अवसर था। इससे पहले खुली किताब वाली परीक्षा मतलब नकल,यही जाना और सुना गया था। परीक्षा में सवाल ऐसे थे कि उनका उत्तर सिर्फ किताबों से देख कर नहीं उतारा जा सकता था। उसके लिए विवेक,कल्पनाशीलता और विश्लेषण करने की क्षमता की आवश्यकता थी। आज जिस तरह की परीक्षाएं होती हैं,उनमें विश्लेषण का शायद ही कोई स्थान होता है,वह सिर्फ तथ्य आधारित होती हैं। पिछले दिनों सीबीएसई ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया,जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नवीन कक्षा का ओपन बुक एजाम यानी खुली किताब वाली परीक्षा होगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। मगर तभी संभव होगा,जब उस विधि से पढ़ाने की पर्याप्त तैयारी होगी और इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता और विवेक का इस्तेमाल करने की



विजय राय

या पारंपरिक हनर यह विज्ञान हनर का ज्ञान हो, वास्तव में एक तरह से खुली किताब वाली ही परीक्षा थी,जहां जीवन को एक किताब के रूप में खोल कर उतर देने की अनुमति थी। तब ज्ञान बंद किताब तक सीमित नहीं था,बल्कि किताबों का ज्ञान जीवन की ओर उन्मुख था।

साधारण अर्थों में खुली किताब वाली परीक्षा का मतलब है वैसी परीक्षा जहां छात्र किताबें खोल कर उत्तर लिखने को स्वतंत्र हों,उसे नकल नहीं माना जाएगा। एक संदर्भ के साथ इस पर बात की जा सकती है। है। दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में में स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा में एक प्राध्यापक ने ओपन बुक एजाम रखा,यानी खुली किताब वाली परीक्षा। उसमें एक विषय के पहले सत्र की पहली परीक्षा में छात्रों को प्रश्न देते हुए कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी किताब को खोल कर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न मुश्किल से छह रहे होंगे और उनमें से छात्रों को सिर्फ दो या तीन प्रश्न हल करने थे। छात्रों ने प्रश्न देखा और किताबें खोलने लगे। प्राध्यापक मुस्कुरा रहे थे,छात्रों को किताबों में झांके हुए देख कर छोटे शहरों से आए छात्र छात्राओं के लिए खुली किताब वाली परीक्षा देने का यह प्रथम अवसर था। इससे पहले खुली किताब वाली परीक्षा मतलब नकल,यही जाना और सुना गया था। परीक्षा में सवाल ऐसे थे कि उनका उत्तर सिर्फ किताबों से देख कर नहीं उतारा जा सकता था। उसके लिए विवेक,कल्पनाशीलता और विश्लेषण करने की क्षमता की आवश्यकता थी। आज जिस तरह की परीक्षाएं होती हैं,उनमें विश्लेषण का शायद ही कोई स्थान होता है,वह सिर्फ तथ्य आधारित होती हैं। पिछले दिनों सीबीएसई ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया,जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नवीन कक्षा का ओपन बुक एजाम यानी खुली किताब वाली परीक्षा होगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। मगर तभी संभव होगा,जब उस विधि से पढ़ाने की पर्याप्त तैयारी होगी और इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता और विवेक का इस्तेमाल करने की

स्वतंत्रता होगी। पढ़ने और पढ़ाने का ऐसा तरीका हो, जहां विद्यार्थी के विश्लेषण,आलोचनात्मक दृष्टि एवं सोच की शक्ति को दबाया न जाए,बल्कि विकसित किया जाए। प्रश्न के रटे-रटायें उत्तर नहीं देने पर अनुगीर्ण हो जाने का डर विद्यार्थी को न सताए। कौना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शिक्षक ओपन बुक एजाम कला को को जानता ही न हो, या उसके मर्म को समझता ही न हो,तो इस परीक्षा की जो विश्लेषण है,वह मर जाएगा और उसका उद्दा असर होगा। खुली किताब वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं,जिसका उत्तर किसी किताब या नोट बुक से सीधे नहीं उतारा जा सकता। इसके लिए विद्यार्थियों को पढ़े विषय की जानकारी का इस्तेमाल अपने विवेक से करते हुए उसे ज्ञान में तब्दील कर उत्तर लिखना होता है। कोई भी शिक्षा जब विवेक, बुद्धि और कल्पना के साथ व्यवहार में लाई जाती है, तो वह ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। खुली किताब वाली परीक्षा इसका एक माध्यम हो सकती है। वास्तव में शिक्षा में जब संवाद का स्थान बने,तभी खुली किताब वाली परीक्षा का कोई मतलब बनता है की उस एक शिक्षक जब संवाद स्थापित करने में सफल होता है,तो सीधे-साधे रटी-रटाई पद्धति पर प्रश्न पड़ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें,इसके बजाय यह पूछा जाना महत्वपूर्ण है कि आज के समय में अगर महात्मा गांधी होते तो ये किस तरह के बदलाव का प्रयास करते। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक विद्यार्थी न सिर्फ महात्मा गांधी के काम का विश्लेषण करने में सक्षम होता,बल्कि वह देश की वर्तमान स्थिति को भी समझने में सक्षम करता और उसके भीतर वर्तमान में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता के महत्व की समझ भी विकसित होती साथ उसके भीतर एक नागरिक होने की जिम्मेदारी का बोध भी आता। जहां तक खुली किताब वाली परीक्षा का संदर्भ है,तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देना हो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें,तो खुली किताब से विद्यार्थी हूबहू उत्तर उतार सकता है और वह नकल ही कहलाएगी।

जाते हैं। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस धरती का कण-कण सूर्य देव के उदित होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। सूर्योदय होते ही हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन विभिन्न फलों के साथ-साथ ठेकुर का प्रसाद मिलता है। हमारे हृदय में ठेकुआ के लिए एक अलग ही प्रेम है। इस ठेकुआ को पाने की प्रतीक्षा हम 1वर्ष करते हैं और यह पाकर मन तुस हो जाता है। लोग काम करने के लिए अपने शहर से कितने ही दूर क्यों न हो,यह पर्व उन्हें अपने गाँव बुला ही लेता है। घाटों की साफ-सफाई इत्यादि का कार्य सभी छोटे-बड़े मिलकर करते हैं,जो हमारे सामाजिक सौहार्द और एकता को दर्शाता है। कहते हैं कि माता सीता और सूर्यपुत्र कर्ण ने भी यह पर्व किया था। यह पर्व संयम,अनुशासन एवं पवित्रता का प्रतीक है। इस पर्व में कोई भेदभाव नहीं होता अमीर हो या गरीब,सभी छठ घाट पर एक साथ अर्घ्य देते हैं।

हमारा महापर्व छठ पूजा

पर खुशी दिखती है,और इसका कारण है हमारी प्रतीक्षा;अर्थात हम लोग इस महापर्व की प्रतीक्षा पूरे वर्ष करते हैं। छठी मईया की महिमा का बखान करते हुए स्व. शाशदा सिन्हा जी ने जिन गीतों को आपनी मधुर आवाज दी है,ऐसा लगता है कि इन गीतों को गाते समय छत्री मईया ने स्वयं उनके सिर पर अपना हाथ रखा है। स्व. शाशदा सिन्हा जी तो आज हमारे बीच नहीं हैं,लेकिन उनके गीत सदियों तक अमर रहेंगे। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की महिमा जितनी लिखी जाए कम है। इस पर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है जिसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस नहाय-खाल को हम लोग कढ़ू-भात के नाम से भी जानते हैं। इस दिन कढ़ू-भात के महाप्रसाद की परंपरा है,जो सात्विक भोजन होने के कारण न सिर्फ हमारे मन को प्रसन्न रखता है बल्कि इस

पर्व की पवित्रता को भी दर्शाता है। द्वितीय दिवस को हम खरना या लोहंड के नाम से जानते हैं। इस दिन ब्रतियाँ पूरे दिन भूखे रहकर शाम में खीर या रसिया का महाप्रसाद बनाती हैं। इस प्रसाद को पाकर जहाँ हमारा मन तुस हो जाता है,वहीं ब्रतियाँ इसे ग्रहण कर आरंभ करती हैं अपना 36 घंटों का निर्जला उपवास। तृतीय दिवस अर्थात संध्या अर्घ्य के दिन हम माथे पे टडरा लेकर घाटों पर जाते हैं। माथे पे टडरा लेकर जाना स्वयं में अल्ट्र उसाह से भरा होता है। इस दिन हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये दृश्य यह दर्शाते है कि उदित हो या अस्त, सूर्य देव सदैव ही हमारे लिए पूजनीय हैं और कोई भी व्यक्ति गिर रहा हो या उठ रहा हो,हम उसकी स्थिति नहीं अपितु उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। चतुर्थ दिवस को हम प्रातः अर्घ्य या पारण करते हैं,जिसमें सूर्योदय से पहले ही सभी लोग घाटों में इकठ्ठा हो



चन्दन केशरी

जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी वहाँ के लोगों की संस्कृति व सभ्यता को प्रदर्शित कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है,वैक उसी प्रकार हमारे बिहार,झारखंड और उत्तर प्रदेश का महापर्व छठ पूजा हमारी संस्कृति व सभ्यता को प्रदर्शित कर सभी को अपनी ओर खींच लेता है। यूँ तो हम लोग अनेकों पर्व-त्योहार मनाते हैं, लेकिन पर्वों में महापर्व केवल छठ पूजा को कहा गया है। यह पर्व छत्री मईया और सूर्य देव को समर्पित है। कार्तिक मास के आरंभ से ही छठ पूजा के गीत हमारे कानों तक पहुँचकर हृदय में एक विशेष अनुभूति जागृत कर यह बताते हैं कि हमारा महापर्व छठ आ रहा है और इन गीतों को सुनकर हम सभी के चेहरे

मोदी के आगमन पर मोदी की गारंटी का मान रखे मुख्यमंत्री

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को राज्योत्सव आयोजन के अवसर पर पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए केन्द्र के समान जुलाई 25 से बकाया 3% प्रतिशत डीए डीआर को एरियर सहित कुल 58% प्रतिशत के आदेश करने की मांग की है। राज्योत्सव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर मोदी की गारंटी को पूरा कर उनका मान रखने का आग्रह किया है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारीगण राज्योत्सव में महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत (डीए डीआर) के आदेश के तदुत्तर में हैं। भाजपा शासित गुजरात,उत्तर प्रदेश,राजस्थान,उत्तराखंड,और बिहार सरकार ने भी एरियर सहित 58% प्रतिशत के आदेश जारी कर दिए हैं। परंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जानबूझकर आदेश जारी करने में पूर्व की भांति विलंब किया जा रहा है जिसके कारण राज्य में कर्मचारियों व पेंशनरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार जुलाई 25 से बकाया 3% प्रतिशत को एरियर सहित देने का आदेश जारी करने संबंधी निर्णय कर राज्योत्सव में घोषित करने की मांग की है। जारी संयुक्त विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख दीपदी यादव पथलगांव जरापुर,राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर,पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोहलानी,प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एच दमसेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार निवेदी रायपुर,राजेश करपण बिलासपुर,गुरुचरण सिंह अमरावती, आर एन ताटी जगदलपुर,बी के वर्मा दुर्ग,केंद्रीय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी प्रकाश के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा रायपुर,सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित प्रकाश के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक रायपुर तथा प्रदेश के विभिन्न जिले से खोइस राम करपण बलौदाबाजार,आर जी बोहरे रायपुर,आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव,राकेश जैन बिलासपुर,परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांण,मेमेश नंदे जशपुर,अभव शंकर गौहाहा रागगढ़, देवनारायण साहू सारांगढ़,एम एल यादव कोरबा,ओ पी कांकेर,आर डी झाड़ा बीजापुर,एस के देहरी नारायणपुर,एस के धातोई कोंडगांव,रूपकुमार झाड़ी दंतेवाड़ा,शेख कासिमूद्दीन सुकमा,प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर,माणिक चंद अंबिकापुर,राजेन्द्र पटेल बलरामपुर,संतोष उकूरू सूरजपुर,आर ए शर्मा गैरला पेंड्रा मरवाही,शिवशेखर सिंह मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर,हरिप्रसाद मिश्रा सकती,भैरालाल परिहार मुगेली,पी ओर साहू दुर्ग,यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा,रिखीराम साहू महासमुंद,लखन लाल साहू गरियाबंद,रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम,देवदत्त दुबे खोरागढ़ छुहूखदान गंडई आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एरियर सहित जुलाई 25 से राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों के लिए भी स्वीकृत कर तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक



गृह मंत्री जी,यह क्या चल रहा है आपके विभाग में? एसपी का स्थानान्तरण और वह जाने से पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर गए?

- एमसीबी पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मनमानी पर उठे सवाल...जाते-जाते कर दिया ‘चहेतो’ का उद्धार ?
- क्या जाते-जाते एमसीबी के तत्कालीन एसपी अपने चहेते पुलिसकर्मियों पर उपकार करते गए...थाना दिलाते गए ?

इधर पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण आदेश आया उधर जाते-जाते उन्होंने अपने जिले के पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिया?

दैनिक घटती-घटना की खबर पर एक बार फिर लगी मोहर,112 में पदस्थ हुए मायावी प्रधान आरक्षक...

जिस दिन स्वयं का स्थानान्तरण हुआ ठीक उसी दिन अपने जिले के पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण करना क्या नियम विरुद्ध नहीं?

—संवाददाता—
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर,25 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के गृह मंत्री से यह सवाल अब होने लगा है की जब पुलिस विभाग में कई जिलों के एसपी को बदल गये हैं,इस बदलाव के दौरान एमसीबी जिले के एसपी का स्थानान्तरण भी हुआ,यह आदेश 24 अक्टूबर को आया,ठीक उसी दिन तत्कालीन एसपी चंद्रमोहन सिंह ने इस जिले के कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश भी जारी कर दिया,क्या ऐसा करना सही है,क्या इस पर छत्तीसगढ़ गृह विभाग संजान लेगा? वैसे इस मामले में कुछ पुलिस अधीक्षकों का कहना है कि यह गलत है,यदि आपको पता है कि आपका स्थानान्तरण होना है तो आपको इस प्रकार का आदेश नहीं निकलना चाहिए,ऐसा पहले नहीं होता था पर ऐसे अब हो रहा है,मतलब कि यह एक नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है। एमसीबी जिले के तत्कालीन एसपी का स्थानान्तरण सूची में नाम देखकर लोग चुटकी भी ले रहे हैं उनका कहना है कि वह तो ठीक हुआ कि अपने विदाई समारोह में जिले की आंतरिक तबादला सूची नहीं जारी की उन्होंने,यह दूसरी बार ऐसा इन्होंने किया है एक बार कोरिया जिले में रहते हुए और दूसरी बार एमसीबी जिले में रहते हुए,सूची भी छेटी नहीं है,काफी लंबी-चौड़ी है,दो पन्ने की सूची है,जिसमें 51 पुलिसकर्मियों के नाम हैं। बताया यह भी जाता है की पुलिस अधीक्षकों का जब स्थानान्तरण होना रहता है तो उन्हें इस बात की जानकारी पहले हो जाती है इसीलिए वह स्थानान्तरण के एक महीने के अंतराल में सूची निकालने से बचते हैं,पर यह ऐसे पुलिस अधीक्षक हैं जो अपने चहेतों के लिए जो इनके लिए तरह-तरह के काम करते हैं उनके लिए यह जाते-जाते एक उपहार स्वरूप ऐसी सूची निकाल कर जाते हैं? जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण आदेश के ठीक बाद जिस तेजी से पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं, उसने विभागीय पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं? आरोप है कि जाते-जाते एसपी साहब ने अपने चहेते पुलिसकर्मियों का उद्धार करते हुए उन्हें मनपसंद थाने और चौकियों की जिम्मेदारी सौंप दी। इस बीच उप निरीक्षक घर के पुलिस थाने पहुंच गए और बड़े पुलिस थाने के प्रभारी बन गए वहीं निरीक्षक हाथ मलते रह गए,वैसे माना जा रहा

है कि उद्धार परस्पर वाला यहां किया गया है।
पूर्व आईजी के स्थानान्तरण आदेश को चार महीने में ही गलत ठहरा कर सभी कर्मचारियों को इन एसपी महोदय ने वापस बुला लिया...

सरगुजा संभाग के पूर्व आईजी ने सरगुजा संभाग में बेहतर पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए उन पुलिसकर्मियों को इशर उभर किया था जो वर्षों से एक ही जगह या जिले में पदस्थ थे और जिनकी कार्यप्रणाली से विभाग की छवि घुमिल हो रही थी और पुलिस पर से लोगों का जिन पुलिसकर्मियों की वजह से कमजोर हो रहा था,ऐसे दोषपूर्ण कार्यप्रणाली वाले पुलिसकर्मियों को इन एसपी महोदय ने चार महीने में ही वापस बुलाने के लिए प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने सहमति प्रदान किया,एक तरह से इन्होंने पूर्व आईजी के स्थानान्तरण आदेश को गलत ठहराया,ऐसा करके इन्होंने कहीं को वापसी के लिए सहयोग किया,यह पुलिसकर्मी पुनः या तो पुराने जिले में आकर फिर से दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के साथ काम कर रहे हैं या अगल बगल के जिले में वह काम कर रहे हैं,पुलिस विभाग के दोषपूर्ण कार्यप्रणाली वाले पुलिसकर्मियों के लिए एसपी साहब एक ढाल थे जो उनके लिए बेहतर प्रयास करते थे।

मायावी प्रधान आरक्षक फिर हुए पोस्ट,112 में मिली जिम्मेदारी

दैनिक घटती-घटना को जब भी कोई जानकारी मिली है वह हमेशा सच ही साबित होती है,मायावी प्रधान आरक्षक के एमसीबी जिले आने से लेकर उनकी वर्तमान पोस्टिंग तक की बात सही हो गई,दैनिक घटती-घटना ने खबर प्रकाशित कर यह बताया था कि पूर्व आईजी ने जिन विवादित पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण जिले से बाहर किया था उन्हें वर्तमान पुलिस अधीक्षक द्वारा वापस लाया जा रहा है,और वह हुआ भी,और ऐसे लोग आए भी,इस खबर में यह भी बताया गया था कि मायावी प्रधान आरक्षक को 112 की जिम्मेदारी मिलेगी जो तत्कालीन एसपी ने जाते-जाते आदेश जारी करके बता दिया की घटती घटना अखबार को मिलने वाली जानकारी सही होती है,सच्ची होती है एक बार फिर उस खबर पर मोहर लगा दी है। जिले के 112 आपातकालीन सेवा में पदस्थ एक मायावी प्रधान आरक्षक को फिर से मनचाही जिम्मेदारी मिली है। बताया जा रहा है कि यह वही प्रधान आरक्षक हैं,जिन्हें पूर्व में भी विशेष परिस्थितियों में पोस्टिंग का लाम मिला था। खबर यह भी है कि जिस दिन तत्कालीन एसपी का स्थानान्तरण आदेश जारी हुआ,उसी दिन इन आरक्षक का भी जादुई पुनः प्रवेश हुआ।

कोरिया पुलिस अधीक्षक,मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर (अप) 112 जिले				
112 जिले				
क्र.सं.	नाम	पद	स्थान	स्थान
1	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
2	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
3	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
4	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
5	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
6	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
7	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
8	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
9	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
10	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
11	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
12	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
13	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
14	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
15	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
16	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
17	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
18	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
19	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
20	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
21	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
22	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
23	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
24	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
25	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
26	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
27	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
28	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
29	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
30	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
31	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
32	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
33	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
34	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
35	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
36	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
37	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
38	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
39	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
40	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
41	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
42	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
43	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
44	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
45	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
46	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
47	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
48	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
49	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
50	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर
51	महेश	डी.डी.	भरतपुर	भरतपुर

अब वर्तमान एसपी क्या पूर्व तत्कालीन एसपी के स्थानान्तरण आदेश उपरंत स्थानान्तरित पुलिसकर्मियों से बेहतर कार्य ले पाएंगी...

जब किसी जिले में नए पुलिस अधीक्षक का आगमन होता है वह अपने अनुसार परीक्षण कर यह तय करता है कि कौन सा पुलिसकर्मी किस जगह या पुलिस थाने के लिए उपयुक्त होगा और कैसे जिले की पुलिसिंग बेहतर होगी,एमसीबी जिले में पुराने पुलिस अधीक्षक ने ही जाते जाते स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिया और उन्होंने यह तय कर दिया कि नए को किस पुलिसकर्मी से कहाँ कहाँ काम लेना है,नए पुलिस अधीक्षक के हाथ में आते ही ऐसे अधिकार नहीं होंगे कि वह जल्द तबादला कर पुलिसकर्मियों को अपने अनुसार जिले की बेहतर पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल कर सके। वैसे अब देखना है कि क्या नई पुलिस अधीक्षक क्या पुराने पुलिस अधीक्षक की पसंद वाले पुलिसकर्मियों से बेहतर काम ले पाती हैं। वैसे पुराने पुलिस अधीक्षक ने बेहतर पुलिसिंग के लिए परीक्षण आधारित तबादला नहीं किया है,जारी तबादला सूची साफ तौर बताती है कि यह मनचाही पदस्थापना प्रदान करके जारी की गई सूची है,गृह विभाग थाना भी इस तबादले में प्रदान किया गया है और कई अन्य को भी मन मांगी मुगद पदस्थापना बतौर प्राप्त हुई है।

स्थानान्तरण आदेश के साथ ही शुरू हुआ ‘ओपरेशन पोस्टिंग’?

सूत्र बताते हैं कि जैसे ही वरिष्ठ मुख्यालय से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण आदेश जारी हुआ,उसी दिन जिले के भीतर कई आरक्षक,प्रधान आरक्षक और उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए गए। यह बात विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है कि जब कोई अधिकारी स्वयं ट्रांसफर पर हो,तो क्या उसे अपने अधीनस्थों की पोस्टिंग बदलने का अधिकार होना चाहिए? विभागीय नियमों के जानकार कहते हैं कि सामान्यतः ऐसे आदेश स्थानान्तरण प्रभाव होने के बाद नए पदस्थ अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। लेकिन यहां ठीक उल्टा देखने को मिला,मानो विदाई से पहले चुने हुए लोगों को उपहार मिल गया हो।

उप निरीक्षक को मिला बड़ा थाना,निरीक्षक हाथ मलते रह गए

स्थानान्तरण सूची में कुछ नामों ने सबको चौंकाया। एक उप निरीक्षक को सीधे मुख्य थाना प्रभारी का चार्ज दे दिया गया,जबकि उसी जिले के वरिष्ठ निरीक्षक हाथ मलते रह गए। विभाग के अंदर यह चर्चा तेज है कि यह शिक्का स्या निरकटता का परिणाम था? वैसे पुलिस थाने के साथ घर का पुलिस थाना मिला यह भी चर्चा है,वैसे माना जा रहा है जैसी चर्चा भी है कि उप निरीक्षक जुगाड़ और संबंध बनाने में माहिर हैं और सत्ता से जुड़कर अपना लाभ तय करना उन्हें बखूबी आता है जो उनकी खूबी है।

जिले में चर्चा,मुख्यालय मोन पूरा मामला फिलहाल चर्चा में है। हालांकि पुलिस मुख्यालय से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं,जिले के अंदर कुछ अधिकारी मानते हैं कि स्थानान्तरण सूची की समीक्षा प्रशासनिक शुचिता के दृष्टिकोण से आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ सरकार गृह (पुलिस) विभाग महानगरी भवन, नया रायपुर, अटल नगर // आदेश //		
नया रायपुर, दिनांक-24/10/2025		
क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थान
(1)	(2)	(3)
1	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर
2	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर
3	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर
4	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर
5	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर
6	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर
7	डी.डी. महेश	पुलिस अधीक्षक, मनोपंचम-चिरमिरी-भरतपुर



पूर्व आईजी के आदेश को चुनौती

सरगुजा संभाग के पूर्व आईजी ने जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए स्थानान्तरण किया था,जिसे तत्कालीन एसपी ने चार महीने में बदल दिया।

विश्वसनीयों को विशेष लाभ

एक प्रधान आरक्षक को जशपुर में रोका गया,जबकि दूसरे को मनेंद्रगढ़ लौटने में रुवि दिखाई गई।

नए एसपी की चुनौती

नए पुलिस अधीक्षक के लिए अब यह चुनौती होगी कि पुराने एसपी की पसंद वाले कर्मचारियों से बेहतर कार्य लिया जा सके।

विरलेषण

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह चलन जारी रहा,तो न केवल विभागीय निष्पक्षता प्रभावित होगी बल्कि मनोबल पर भी असर पड़ेगा। 'जाते-जाते पोस्टिंग' के इस नए रूप ने पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया है।

जिले में चर्चा

इस घटनाक्रम ने जिले में हलचल मचा दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला-सूरजपुर (80700)	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (त.) उदयपुर, जिला- सरगुजा,83040
स09प्र0क्र01512/ ब/ -12/1/2024 सूरजपुर, दिनांक-23.10.2025	ईश्वरहार पुत्रद्वारा सर्व साधारण ग्रामवासी, ग्राम सिंगीटाना, तहसील लखनपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक उसील राम पिता हुबलाल ग्राम सिंगीटाना, तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा के द्वारा उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम सिंगीटाना, तहसील उदयपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 360/4 रकबा 0.151 हेक्टर में से रकबा 0.081 हेक्टर का औद्योगिक प्रयोजन में व्यवर्तन स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया गया है। उक्त व्यवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो ईश्वरहार प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा अथवा आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।
सील तहसीलदार सूरजपुर जिला- सूरजपुर	सील अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर,जिला-सरगुजा

भ्रष्टाचार जांच में साबित होने के बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटना बेखौफ!

जांच में भ्रष्टाचार साबित...कार्यवाही शून्य...पुनः लौटे सीएमओ और अब सबूत मिटाने में जुटे...

- भ्रष्टाचार जांच में साबित होने उपरांत भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटना बेखौफ,आखिर किसका है संरक्षण ?
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुनः पहचा पटना,अब कर रहा है भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने का प्रयास:सूत्र
- वया भ्रष्टाचार ही है असली सुशासन,वया भ्रष्टाचारियों को मिलता रहेगा संरक्षण ?
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी का इतना प्रभाव इतनी दहशत की एसडीएम भी कलेक्टर के आदेश उपरांत नहीं कर रहे जांच

—संवाददाता—
कोरिया/पटना,25 अक्टूबर 2025
(घटती-घटना)।

नव गठित नगर पंचायत पटना में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। जांच में भ्रष्टाचार साबित हुआ,लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वह पुनः नगर पंचायत लौट आया और अपने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है। जांच उपरांत सीएमओ के भ्रष्टाचार की तथ्यात्मक पुष्टि हो चुकी थी,जिसमें मृत मवेशियों के दफन,अलाव निर्माण और टाइल्स का पैसा अपने खाता में खालना शामिल है। इसके बावजूद कार्रवाई शून्य रही। ज्ञात हो की नव गठित नगर पंचायत पटना में उसके गठन से लेकर अब तक भ्रष्टाचार करने वाले नगर विकास निधियों का बंदरबाट करने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच हुई जांच में भ्रष्टाचार साबित भी हुआ लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह पुनः पटना लौट आया और वह अब अपने भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास जारी कर चुका है जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं,जांच उपरांत वह भी नगरीय प्रशासन संभागीय संयुक्त संचालक स्तरीय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की चोरी पकड़ी गई लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही के नाम पर कोई भी बात सामने नहीं आई,अब इसके पीछे किसका हाथ है कौन एक भ्रष्ट और विकास विरोधी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ऐसा हितैषी है जो उसे संरक्षण प्रदान कर रहा है जिसके लिए नव गठित नगर पंचायत पटना की जनता से भी अधिक महत्वपूर्ण है मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटना,क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर की

जनता से भी अधिक चेहेता हो गया उसे संरक्षण प्रदान करने वाले के लिए,ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब किसी के पास नहीं है,मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बिना निर्माण किए निर्माण का भुगतान कर दिया,बिना टाइल्स लगाए टाइल्स का पैसा जेब में डाल लिए एक जेसीबी फर्म के साथ मिलकर मृत मवेशियों के कफ़न दफन का झूठा पैसा निकाल लिया और इतना ही नहीं झूठा अलाव जलाया लोगों की ठंड दूर करने की बजाए अपनी जेब गर्म किया,दैनिक वेतन भोगी कुछ कर्मचारियों को भी चोरी में शामिल किया उनके बैंक खाते में नगर विकास निधि का पैसा डाला और उन्हें कमीशन देकर उसे भी अपनी जेब में डाल लिया और बेखौफ होकर नगर को लूटने का काम करता रहा,वैसे जांच उपरांत जो तथ्य जांच में सामने आए वह भ्रष्टाचार को साबित कर गए लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई बल्कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुछ दिन इशर उधर मुंह छिपाकर जुगाड़ लगाकर पुनः लौट आया और वह अब अपने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने में भीड़ चुका है,वैसे स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना यह सदेह उत्पन्न करता है कि किसी न किसी का संरक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्राप्त है जो उसे नगर को दुर्दशा की स्थिति तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। वैसे जिले के आला अधिकारी,अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब कुछ जानकर मौन हैं और वह भी केवल मूक दर्शक बने हुए हैं जैसे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी खुद के विकास के लिए स्वतंत्र हैं,वैसे वर्तमान परिदृश्य में यह लगातार देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार ही सुशासन की पहचान बनी हुई है जिसमें रोक टोक का प्रयास शून्य है।



स्पष्ट भ्रष्टाचार साबित होने उपरांत भी नहीं हुई मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर कार्यवाही

नव गठित नगर पंचायत अपने गठन और गठन उपरांत पदस्थ सीएमओ के भ्रष्टाचार से आरंभ से ही ग्रसित है जो साबित हो चुका है,कभी मृत मवेशियों के मामले में भ्रष्टाचार जेसीबी फर्म के साथ मिलकर हुआ,कभी ठंड में अलाव के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ,कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बैंक खाते का भी भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल हुआ,हद तो तब हुई जब पुराने भवन में रंगाई-पोताई मात्र करवाकर भवन निर्माण और सर्व सर्वसुविधा युक्त बनाने के नाम से लाखों निकाल दिए गए,मामले में शिकायत हुई जांच भी हुई लेकिन जब कार्यवाही की बात हुई मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुनः नगर पंचायत पहुंच गया और अब वह आगे भी नए भ्रष्टाचार को अंजाम देगा जो झुलटायी नहीं जा सकता।

कलेक्टर के निर्देश पर भी नहीं पहुंचे एसडीएम जांच करने,वया वह मयभीत हैं?

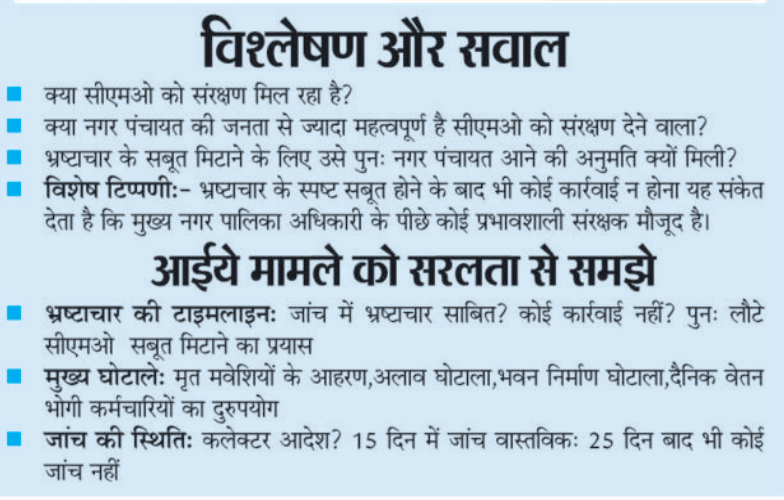
मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटना की शिकायत कलेक्टर कोरिया से भी हुई,कलेक्टर ने एसडीएम को 15 दिवस के भीतर जांच का आदेश दिया,आदेश जारी होने और समय सीमा में पालन के बीच 23 दिनों का समय बीत गया,न एसडीएम नगर पंचायत पहुंचे न उन्होंने जांच ही की,समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हुए मामले में कोई भी जांच एसडीएम ने नहीं की,अब सवाल यह उठता है कि क्या एसडीएम भयभीत हैं,उरे हुए हैं सीएमओ के पीछे की उसकी पकड़ पहुंच से वह अवगत हैं इसलिए वह जांच से खुद किनारे हैं।

मुख्य घटनाक्रम

- जेसीबी फर्म घोटाला: मृत मवेशियों के दफनाने के नाम पर भ्रष्टाचार।
- अलाव घोटाला: ठंड में अलाव जलाने का नाम पर पैसों का गबन।
- भ्रष्टाचार में कर्मचारों शामिल: दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बैंक खाते का दुरुपयोग।
- भवन निर्माण घोटाला: केवल रंगाई-पोताई कर लाखों की निकासी।
- कलेक्टर आदेश पर भी जांच नहीं: कलेक्टर ने 15 दिन में जांच का निर्देश दिया, लेकिन 25 दिन बीतने के बाद एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।

भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने का क्या

मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया गया मौका,पुनः कार्य पर लौटा सीएमओ भ्रष्टाचार के आरोप जांच में सही साबित हुए,अब जब जांच में भ्रष्टाचार साबित हुआ क्यों कार्यवाही नहीं हुई यह बड़ा सवाल है,सीएमओ पुनः नगर पंचायत में आना जाना जारी कर चुका है,क्या उसे भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए छोड़ दिया गया है जिससे लीपापोती वह कर सके। वैसे क्या वह दस्तावेजों को आग के हवाले करने वाला है या उन्हें चोरी गया बताने वाला है, क्या ऐसा कुछ प्रयाजित किए जाने के लिए उसे फिलहाल पुनः नगर पंचायत आने की अनुमति प्रदान की गई है।



कोरिया जिले में सिंचाई क्षमता में ढाई गुना वृद्धि,25 वर्षों में खेती का चेहरा बदला

सिंचाई रकबे में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी,40 हजार से अधिक किसान ले रहे लाभ,कई जलाशयों में नहर मरम्मत और विस्तार कार्य से किसानों को हुआ लाभ

—राजन पाण्डेय—
कोरिया,25 अक्टूबर 2025
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष में कोरिया जिले ने सिंचाई के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। पिछले 25 वर्षों में जिले की कुल सिंचित रकबा में ढाई गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में जिले का सिंचित रकबा 18 हजार 13 हेक्टेयर था,जो अब बढ़कर 21 हजार 102 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यदि सिंचाई प्रतिशत की बात करें तो यह वर्ष 2000 में 13.72 प्रतिशत था,जो अब बढ़कर 34.55 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि जिले की कृषि व्यवस्था और जल संसाधन प्रबंधन में आए सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। रबी फसलों के सिंचाई रकबे में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2000 में जहाँ मात्र 3 हजार



595 हेक्टेयर में रबी फसलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त थी,वहीं अब यह क्षेत्र बढ़कर 5 हजार 469 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। जल संसाधन संभाग,बैकुंठपुर के अनुसार,वर्ष 2000 में जिले में 1 मध्यम और 63 लघु सिंचाई परियोजनाएँ संचालित थीं,वर्तमान में 2025 में यह संख्या 2 मध्यम और 58 लघु परियोजनाओं तक है। इस बीच अविभाजित कोरिया जिले की 43 लघु परियोजनाएँ



नवगठित मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले को हस्तांतरित की गई हैं। वर्ष 2000 में 28 हजार 619 किसान सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित हो रहे थे,जबकि अब यह संख्या बढ़कर 40 हजार 210 तक पहुंच गई है। जिले में वर्तमान में कुल 60 सिंचाई परियोजनाएँ संचालित हैं,जिनमें से 2 प्रमुख हैं। यह उपलब्धि न केवल कोरिया जिले की कृषि उत्पादकता में वृद्धि का प्रतीक है,बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था



की मजबूती और किसानों की जीवनशैली में आए सकारात्मक बदलाव का भी द्योतक है। सिंचाई के क्षेत्र में पूर्व मंत्री रामचन्द्र सिंह देव का अभिनव योगदान: प्रदेश सहित जिले में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में तत्कालीन मध्यप्रदेश में सिंचाई मंत्री रहे एवं छत्तीसगढ़ पूर्व व प्रथम वित्त मंत्री कोरिया कुमार डॉ राम चंद्र सिंह देव को जाता है अविभाजित कोरिया के अधिकांश डेम एवं बांध कोरिया

कुमार दें माने जाते हैं चाहे बैकुण्ठपुर के गेज बांध की बात की जाए या फिर सोनहत के घुनघुड़ा,टेडिया तंजरा जलाशय हो सभी के निर्माण में इनका अभिनव योगदान रहा ,कोरिया के कार्यकाल में सोनहत एवं बैकुण्ठपुर में नहरों का व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ जिससे आज जिले के किसान कहीं न कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। डाऊकाबुड़ा जलाशय नहर निर्माण से किसानों की बदली जिंदगी: सोनहत विकासखण्ड मुख्यालय के डाऊकाबुड़ा जलाशय में 2023 में हुई पक्की नहर निर्माण से सोनहत क्षेत्र के किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ हुआ सोनहत खुररा पारा सलगवा कला भेलवाड़ाण्ड आदि क्षेत्र में नहर निर्माण होने से किसानों को धान की फसल में भारी फायदा हुआ,अब पानी सीधे

किसानों के खेतों तक पहुंचने लगा है। किशोरी जलाशय निर्माण से लोगों को सिंचाई के साथ मिला रोजगार: सोनहत के किशोरी जलाशय निर्माण होने के बाद किसानों को फसल के साथ रोजगार भी मिला,धान एवं गेहूँ के फसल के लिए यह जलाशय वरदान साबित हुआ,क्षेत्र के ग्रामीण यहां खेती के साथ मछली पालन भी कर रहे हैं जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। तंजरा में हो रहा दो फसली खेती: तंजरा जलाशय में किसान दो फसली खेती कर लाभ ले रहे हैं,यह जलाशय भी खूब डार राम चन्द्र सिंह देव के प्रयासों से निर्मित हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार में नहर मरम्मत और वेस्ट वियर से लीकेज की समस्या ठीक होने के बाद पानी नहरों से पानी पर्याप्त मिलने लगा है।

हर्षित राणा,रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज स्वीप से रोका

ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की

सिडनी, 25 अक्टूबर 2025। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार का दिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यादगार रही, जब पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार पारियों ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की सीरीज जीत से रोक दिया। रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक जड़ा, जबकि कोहली ने संगकारा को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोनों दिग्गजों ने जनवरी 2020 के बाद पहली बार किसी भी प्रारूप में शतकीय साझेदारी की और भारत को नौ विकेट से शानदार जीत दिलाई। इससे पहले, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा (4/39) की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 236 रनों पर ढेर कर दिया। मैथ्यू रेंसों (56) ही अकेले जूझते नजर आए, जबकि भारतीय गेंदबाजों-हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने सभी हुई गेंदबाजी से मेजबान टीम की कमर तोड़ दी।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने किया संघर्ष

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय उलटा पड़ गया। मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड (31) को आउट कर शुरुआती झटका दिया। मार्श ने कुछ समय तक टिके रहते हुए 41 रन बनाए, पर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ट हो गए। रेंसों और मैथ्यू शॉर्ट ने बीच में साझेदारी बनाई, लेकिन सुंदर और अक्षर की कसी हुई गेंदबाजी ने रन गति थाम दी। शॉर्ट (28) का विकेट ऑस्ट्रेलिया के शानदार कैच से गिरा, जबकि श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का अविश्वसनीय कैच पकड़कर सभी को चौंका दिया। हालांकि इस दौरान उनके बाएँ पसलियों में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रेंसों के अर्धशतक के बाद जैसे ही वे आउट हुए, बाकी बल्लेबाज जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए। हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा ने अंतिम झटके देकर मेजबान टीम की पारी 46.4 ओवर में 236 रन पर समेट दिया।



भारत की जवाबी बल्लेबाजी कोहली-रोहित का क्लासिक शौ

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पावरप्ले में 68 रन जोड़ दिए। गिल (38) के आउट होते ही मैदान में उतरे विराट कोहली, जिन्हें दर्शकों से जबरदस्त स्वागत मिला। शुरुआत में थोड़ी परेशानी के बाद कोहली ने रोहित के साथ मिलकर 168 रनों की एक बेहतरीन नाबाद साझेदारी की। रोहित ने 21वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि कोहली ने 75वां वनडे अर्धशतक जड़ा। दोनों ने मिलकर 19वीं बार वनडे में 100 से अधिक की साझेदारी की। 32वें ओवर में कोहली ने 14,235वां रन पूरा कर संगकारा को पीछे छोड़ा, वहीं अगली ही गेंदों में रोहित ने अपना 33वां वनडे शतक पूरा किया।



रोहित-कोहली ने रन चेज आसान बनाया

रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने भारत के रन चेज को आसान बना दिया। भारतीय ओपनर्स ने 62 बॉल पर 69 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को जोश हेजलवुड ने तोड़ा। यहां गिल 24 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान गिल के आउट होने के बाद रोहित-कोहली की जोड़ी ने भारत को जीत दिला दी।

कंगारुओं ने पावरप्ले में विकेट गंवाया

टॉस जीतकर बैटिंग कर रही ऑस्ट्रेलिया ने पावरप्ले-1 में 67 रन बनाने में एक विकेट गंवाया था। जबकि, मैच के शुरुआती ओवरस में बॉल स्विंग हो रही थी। ऐसे में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने संभलकर बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़ लिए। हेड को मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कराया। यहां ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हुई। पावरप्ले के बाद अक्षर पटेल ने कप्तान मिचेल मार्श (41 रन) को बोल्ट कर दिया। बाद में मैट रेंसों ने 56 और मैथ्यू शॉर्ट ने 30 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 29 और एलेक्स कैरी ने 24 रन बनाए।

लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद रोहित शर्मा ने कहा

जब मैं टीम में आया था, मुझे याद है कि सीनियर्स ने कैसे हमारी मदद की थी, अब यह हमारा काम है कि हम भी वैसा ही करें। हमें अनुभव साझा करना होगा, गेम प्लान बनाने में उनकी मदद करनी होगी। मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मेरी कई अच्छी यादें रही हैं- बेहतरीन पिच, मैदान और दर्शक। मुझे वह करना पसंद है जो मैं करता हूँ और उम्मीद है कि इसे करना जारी रखूंगा।



पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स के बीबीएल में खेलने पर लगी रोक हटी, बाबर आजम समेत ये खिलाड़ी फिर से आएंगे नजर

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2025। विदेशी लोगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रुख को लेकर शुरुआती अनिश्चितताओं के बाद पाकिस्तान के प्रमुख क्रिकेटर्स को आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने की अनुमति मिल गई है। यह फैसला पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद द्वारा सितंबर के अंत में जारी एक नोटिस के बाद आया है, जिसमें खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में शामिल होने से रोक दिया गया था। हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि मामला अब सुलझ गया है और बीबीएल अनुबंध वाले सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी योजना के अनुसार भाग लेंगे।

सीए ने जारी किया बयान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग के हवाले से कहा कि ये निर्णय पिछले हफ्ते ही लिया गया है।



इसलिए वे सभी खेलेंगे, उन्हें खेलने की अनुमति मिल गई है, जिसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। बीबीएल में हमारे कुछ बेहतरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इसलिए हम उन्हें इस गर्मी में यहां देखने के लिए उत्सुक हैं।

ये पाकिस्तानी खिलाड़ी आएंगे नजर

इस सीजन के लिए जिन उल्लेखनीय पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पुष्टि हुई है, उनमें बाबर आजम (सिडनी सिक्सर्स), शाहीन

शाह अफरीदी (ब्रिस्बेन हीट), हसन अली (एडिलेड स्ट्राइकर्स), मोहम्मद रिजवान (मेलबर्न रेनेगेड्स), हारिस रऊफ (मेलबर्न स्टार्स) और शादाब खान (सिडनी थंडर) शामिल हैं। ये टूर्नामेंट 14 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा, और प्रशंसक विशेष रूप से 5 जनवरी और 18 जनवरी को बाबर और शाहीन के बीच होने वाले मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस बार बीबीएल में रविचंद्रन अश्विन भी सिडनी थंडर के लिए पूरा सीजन खेलेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध है, जिसने विदेशी लोगों में भारतीय खिलाड़ियों की भविष्य की भागीदारी के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। जब ग्रीनबर्ग से पूछा गया कि क्या और भारतीय खिलाड़ी अश्विन के नक्शेकदम पर चल सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह अल्पकालिक और मध्यम अवधि में यथार्थवादी है। हम बातचीत जारी रखेंगे।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2025। आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलने इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम की खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना गुरुवार को सुबह खजराना रोड पर हुई, जब खिलाड़ी अपने होटल से बाहर निकलकर पास के एक कैफे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवाल व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें से एक क्रिकेटर को गलत तरीके से छुआ।

व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज : अपनी शर्मानाक हरकत को अंजाम देकर व्यक्ति फरार हो गया। इसके बाद खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को इस घटना के बारे में बताया। सिमंस ने स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी सहायता के लिए एक वाहन की व्यवस्था की। शिकायत के बाद सहायक पुलिस आयुक्त ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और कानूनी कार्रवाई शुरू की। एमआईजी पुलिस थाने में धारा 74 और 78 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना के दौरान एक युवक ने छेड़छाड़ करने



वाले व्यक्ति के मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया, जिसके बाद शुक्रवार को आरोपी अकील खान की तुरंत पहचान हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अकील के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और घटना की आगे की जाँच की जा रही है। विषय कप में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंदौर में दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह खबर इंदौर के होल्कर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच से कुछ घंटे पहले आई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 5 में जीत हासिल की है। एक मुकाबला बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया।

श्रेयस अय्यर कैच लेने के दौरान हुए चोटिल, रिब केज में लगी चोट



सिडनी, 25 अक्टूबर 2025।

भारत के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान बाईं पसलियों (रिब केज) में चोट लग गई। बीसीसीआई ने बताया कि अय्यर को आगे की जाँच और मूल्यांकन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यह घटना सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की पारी के 34वें ओवर में हुई, जब अय्यर ने एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा। कैरी ने हर्षित राणा की गेंद पर सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज होकर हवा में चली गई। गेंद बैकवुर्ड प्लाइट और डीप थर्ड मैन के बीच गिरने वाली थी, लेकिन अय्यर ने लंबी दौड़ लगाते हुए पीछे

की ओर डाइव लगाकर अद्भुत कैच लपका। कैच लेते वक्त अय्यर जोर से जमीन पर गिरा। फिजियो को मैदान पर बुलाया गया और अय्यर को कुछ देर बाद मैदान से बाहर ले जाया गया। वह इसके बाद पूरे मैच में मैदान पर वापस नहीं लौटे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 236 रन पर 46.4 ओवर में ऑलआउट हो गई। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा (नाबाद 121) और विराट कोहली (नाबाद 74) की 168 रनों की अटूट साझेदारी की बदौलत लक्ष्य को 39वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी। हालांकि इसके बावजूद श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम की।

हॉकी इंडिया लीग 2025-26 सीजन का शेड्यूल जारी, तीन शहरों में होंगे मैच

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2025। हीरो हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) ने शनिवार को अपने 2025-26 सीजन के पुरुष और महिला लीग के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा की। भारत की इस प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता के नए सीजन की घोषणा रांची स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोर्ट हॉकी स्टेडियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदीप्य कुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव एवं हीरो हॉकी इंडिया लीग गर्वनिंग कमेटी के सदस्य भोला नाथ सिंह, रांची रॉयल्स टीम के मालिक अलविश एम.ए., तथा अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह, आशिष तानी पुर्ति, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेण, निकी प्रधान और ब्यूटी डुंग-डुंग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रांची रॉयल्स टीम का नया आधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया गया, जो झारखंड की समृद्ध हॉकी परंपरा और ऊर्जा का प्रतीक है।



पुरुष और महिला लीग का कार्यक्रम : इस बार पुरुष लीग तीन प्रमुख शहरों चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में आयोजित होगी, जबकि महिला लीग पिछले वर्ष की तरह पूरी तरह रांची में खेली जाएगी। पुरुषों की हीरो एचआईएल का आगाज 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में होगा, जहाँ मेजबान तमिलनाडु ड्रैगन्स और हैदराबाद तूफान्स के बीच रोमांचक उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। पुरुष लीग में आठ टीमों, तमिलनाडु ड्रैगन्स,

हैदराबाद तूफान्स, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स (पिछली चैंपियन), वेदांता कलिंगा लैंसर्स, रांची रॉयल्स, एसजी पाइपर्स और एचआईएल गर्वनिंग कार्पोरेशन की टीमों हिस्सा लेंगी।

महिला हीरो एचआईएल की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोर्ट स्टेडियम में होगी। उद्घाटन मैच रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। महिला लीग में कुल चार

टीमें रांची रॉयल्स, एसजी पाइपर्स, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, और श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स भाग लेंगी।

तीसरा और अंतिम चरण: भुवनेश्वर (17-26 जनवरी) : सभी टीमों एक-दूसरे से एक बार भिड़ेंगी। शीर्ष चार टीमों प्लेऑफ में पहुंचेंगी, जिनमें क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर (23 जनवरी), क्वालिफायर-2 (25 जनवरी) और फाइनल (26 जनवरी, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर) खेला जाएगा।

भारतीय महिला बेसबॉल टीम चीन खाना इनमें पंजाब की 5 बेटियाँ, अमृतसर की मनवीर कौर उपकप्तान



लुधियाना, 25 अक्टूबर 2025। चीन के हांगजो में महिला बेसबॉल एशिया कप के लिए भारतीय टीम रवाना हो गई। इंडियन बेसबॉल टीम में पंजाब की पांच लड़कियों को जगह मिली है। यही नहीं पंजाब के अमृतसर की मनवीर कौर को टीम में उपकप्तान की जिम्मेदारी भी मिली है। भारतीय महिला बेसबॉल टीम अक्टूबर से 2 नवंबर तक चीन में अलग-अलग देशों के साथ अपने मैच खेलेंगी। भारतीय महिला बेसबॉल की एशिया कप के लिए लुधियाना में भी कुछ देर कैप किया। पंजाब बेसबॉल टीम के कोच व पंजाब बेसबॉल एसोसिएशन के महासचिव हरबीर सिंह गिल ने बताया कि एशिया कप के लिए 20 खिलाड़ियों का दल रवाना हुआ है, उसमें से पांच पंजाब की हैं। उन्होंने बताया कि महिला टीम का दल लुधियाना में प्रैक्टिस करने के बाद चीन के लिए रवाना हुआ।

टूर्नामेंट में एशिया महाद्वीप की 10 टीमों लेंगी हिस्सा: हरबीर सिंह गिल ने बताया कि इस टूर्नामेंट में एशिया महाद्वीप की 10 टीमों हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए महाराष्ट्र की खिलाड़ी रेशमा शिवाजी पुणेकर को भारतीय टीम की कप्तान दी गई जबकि पंजाब की मनवीर कौर को उपकप्तान बनाया गया। टूर्नामेंट में चीन, चीनी ताइपे, हॉन्गकॉन्ग, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड की टीमों हिस्सा लेंगी।

भारतीय टीम में चुनी गई पंजाब की पांच खिलाड़ी: टीम में जो पांच खिलाड़ी चुनी गई हैं, उनमें से दो लुधियाना की हैं और दो अमृतसर की, जबकि एक खिलाड़ी फिरोजपुर की हैं। कोच हरबीर सिंह गिल ने बताया कि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी गरीब घरों से हैं। उन्होंने बताया कि निशु व मनवीर के पिता मजदूरी करते हैं।

मुख्यमंत्री साय पंडवानी महासम्मेलन के समापन समारोह में हुए शामिल

पंडवानी एक ऐसी विधा है,जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को विश्व में मिली पहचान:सीएम साय

रायपुर,25 अक्टूबर 2025। पंडवानी एक ऐसी विधा है,जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। हमारे पंडवानी कलाकारों ने न्यूयॉर्क,पेरिस और लंदन तक महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवित रखा है,बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया है। पंडवानी आज हमारी लोक चेतना,नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम मेड़सरा में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग रायपुर के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव,अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सवाड़ा,छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकार,साजा विधायक ईश्वर साहू,राज्य तेलधानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू एवं जागेश्वर साहू,पूर्व विधायक लाभचंद बाफना एवं डॉ. दयाराम



हमारी सरकार छत्तीसगढ़ी लोककला और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है: साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ी लोककला और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कलाकारों की पेशान राशि में वृद्धि की गई है और अवसरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना का निर्णय लेकर हमने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था,तब उनके मन में विकास के साथ-साथ संस्कृति को संहेजने की भी गहरी मंशा थी। आज जब ऐसा सुंदर आयोजन देखात हूं,तो मन को सुकून मिलता है कि अटल जी की मंशा पूर्ण हुई है।

साहू,जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे तथा दुर्ग नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बाधमार भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज मुझे पंडवानी के पुरोधा स्वर्गीय झाड़ूम देवांगन

जी की स्मृति भी हो रही है। जब वे हाथ में तंबूरा लेकर प्रस्तुति देते थे,तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पंडवानी गायन में महिला कलाकारों की विशेष सफलता उल्लेखनीय रही है। मुझे स्वर्गीय लक्ष्मी बंजारे जी का भी

स्मरण हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारी धरती पर तीन बार्ड जैसी विभूति हुईं,जिनमें पद्मश्री,पद्मभूषण और पद्मविभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। जब वे तंबूरा लेकर आलाप भरती हैं,तो ऐसा लगता है मानो आकाश के देवी-देवता भी उन्हें सुन रहे हों। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैंने अनेक अवसरों पर तीन बार्ड जी को पंडवानी सुनी है। श्याम बेनेगल की भारत एक खोज में उनका पंडवानी गायन दृश्य मन को आनंद और उत्सुकता से भर देता है। पद्मार्डों उषा बारले जी हमारे बीच उपस्थित हैं,जिन्होंने अपने अद्भुत पंडवानी गायन से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडवानी हमारी अमूल्य धरोहर है। आज इस महासम्मेलन के आयोजन के माध्यम से आप सभी ने इस धरोहर को संहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बचपन में रामलीला मंडलियों के माध्यम से रामायण की कथाएं और पंडवानी के माध्यम से महाभारत की कथाएं सुनीं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोककलाकारों ने रामायण और महाभारत जैसी महान कथाओं को जन-जन तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडवानी गायन इस मायने में भी अद्वितीय है कि इसमें स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं है।

रायपुर: राज्योत्सव में 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू

समारोह में भजन सिंगर हंसराज रघुवंशी,बॉलीवुड सिंगर भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण,अंकित तिवारी और अंतिम दिन कैलाश खेर देंगे प्रस्तुति



रायपुर,25 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में राज्योत्सव को धूम-धाम तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। राज्योत्सव में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्य मंच के अतिरिक्त राज्योत्सव स्थल पर बने शिल्प ग्राम में भी करीब 1 हजार छत्तीसगढ़ी कलाकर अपनी अलग-अलग प्रस्तुति देंगे। समारोह में भजन सिंगर हंसराज रघुवंशी,बॉलीवुड सिंगर भूमि त्रिवेदी,आदित्य नारायण, अंकित तिवारी और अंतिम दिन कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे।

राज्योत्सव का उद्घाटन 1नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं राज्योत्सव व प्रधानमंत्री से जुड़े अन्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गंभीरत से कार्य करने की हिदायत दी।

पौष्म के रूट पर सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की रात छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके स्वागत के लिए राजधानी के चौक-चौराहों की 12 थीम में तैयार किया गया है। हर चौराहे पर एक सांस्कृतिक दल मौजूद रहेगा, जो सरगुजा से लेकर बस्तर तक की पारंपरिक झलक पेश करेगा। इसके अलावा राज्योत्सव स्थल के परिक्रमा पथ पर सांस्कृतिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

बिजली के खंभों में तीन रंग की रोशनी

राज्योत्सव के लिए नवा रायपुर को सजाया जा रहा है। जगह-जगह छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा बिजली के खंभों को तीन रंग की रोशनी से सजाया जा रहा है,जो कि देखने में तिरंगा जैसा दिखाई देगा।

5000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ ,वित्त विभाग से मिली मंजूरी

रायपुर,25 अक्टूबर 2025। वित्त विभाग ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है,और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। मुख्यमंत्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को 'नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम' बताया। 5000 पदों हेतु शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी,जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रदेश में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक प्रमुख चुनौती रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सीमित थी। नई भर्ती से इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा,जिससे बच्चों को अब अपने ही गाँव और क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही,यह पहल प्रदेश में शिक्षण के स्तर को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में सहायक सिद्ध होगी। शिक्षा राज्य के विकास की सबसे सशक्त आधारशिला है। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर विद्यालय में योग्य शिक्षक उपलब्ध हों। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त करेगा,बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।



प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्काजाम की घोषणा

रायपुर,25 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ में आज, 25 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 10 प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्काजाम की घोषणा की है।

संगठन के लगभग 3 लाख ड्राइवर आज से स्ट्रेचरिंग नहीं थामेंगे। इसका मतलब है कि पूरे राज्य में परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। ट्रक,बस,टैक्सी और अन्य वाहन सड़कों पर रुक जाएंगे, जिससे हाईवे पर भारी जाम लग सकता है। यह आंदोलन कबीरधाम जिले के कलेक्टर को सीपे गए ज्ञापन के बाद शुरू हुआ है। संगठन ने 25 अक्टूबर



तक मांगें पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी,जो अब अमल में आ गई है। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार उनकी पेशानियां नहीं समझ रही। खासकर, नेशनल हाईवे 130 सी के डोहेल के

पासबड़ी संख्या में ड्राइवर जमा हो गए हैं। वे सड़क पर धरना दे रहे हैं और वाहनों को रोक रहे हैं,इससे माल ढुलाई, यात्री परिवहन और दैनिक जरूरतों की चीजों का आवागमन ठप्प हो सकता है।

बरी होने से दोषी कर्मचारी के विरुद्ध समाप्त नहीं होगी विभागीय कार्यवाही,शासकीय कर्मियों के लिए हाई कोर्ट का अहम फैसला

बिलासपुर,25 अक्टूबर 2025। हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित या अनुचित रूप से विलंबित नहीं किया जा सकता। डीविजन बेंच ने यह भी कहा कि आपराधिक मामले के लंबित रहने से विभागीय कार्यवाही स्वतः जारी रहने या समाप्त होने पर रोक नहीं लगती। ग्रामीण बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बोडो गुरु की डीविजन बेंच ने कहा कि किसी आपराधिक मामले के लंबित रहने से विभागीय कार्यवाही स्वतः जारी रहने या समाप्त होने पर रोक नहीं लगती। इसके चलते विभागीय कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक केवल एक उचित अवधि के लिए ही होनी चाहिए। बेंच ने साफ कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा आपराधिक मुकदमे की लंबी अवधि का उपयोग विभागीय कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए विलंबित



करने के लिए नहीं किया जा सकता। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में कार्यरत कर्मचारी को शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप सामने आए। बैंक की शिकायत पर पुलिस ने ब्रांच में आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस में शिकायत के साथ ही बैंक ने मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। बैंक ने दावा किया कि जांच उचित

प्रक्रिया के तहत की गई,जिसमें आरोपों की जांच,गवाहों से पूछताछ और क्रास एक्जामिनेशन का अवसर प्रदान करना शामिल था। ब्रांच मैनेजर ने विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका में बताया कि जिन आरोपों पर विभागीय जांच की जा रही है, उन्हीं आरोपों पर आपराधिक मुकदमा लंबित है। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने बैंक को निर्देश दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए। हालांकि, बैंक ने जांच प्रक्रिया जारी रखी। उसने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, कारण बताओ नोटिस जारी किया और प्रतिवादी को व्यक्तिगत दायर की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बैंक को निर्देश दिया कि आपराधिक मुकदमे की समाप्ति के बाद ही विभागीय कार्यवाही आगे बढ़ाया जाय। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए बैंक ने डीविजन बैंक के समक्ष याचिका दायर की।

आईएस की शिकायत पर बीजेपी नेता अरेस्ट

रायगढ़,25 अक्टूबर 2025। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को आईएस अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने भाजयुमो नेता पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया है। मामला घरघोड़ा अनुविभाग का है। घरघोड़ा अनुविभाग के ग्राम तिलाईपाली निवासी अजीत गुप्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं। उनके द्वारा एनटीपीसी लारा परियोजना के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पांच दिनों पूर्व भी उन्होंने एनटीपीसी परियोजना के विरोध में आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो जाने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई थी और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। किसी तरह



पुलिस की समझाइश के बाद आंदोलन को समाप्त करवाया गया था। बता दें कि घरघोड़ा अनुविभाग में एसडीएम के पद पर आईएस दुर्गा प्रसाद पदस्थ हैं। वे 2022 बैच के आईएस अधिकारी हैं। मूलतः उड़ीसा के रहने वाले दुर्गा प्रसाद जांजगीर जिले में प्रोबेशनर रहे हैं। रायगढ़ के घरघोड़ा में एसडीएम हैं। भाजयुमो नेता अजीत गुप्ता ने आंदोलन के कुछ दिनों बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर घरघोड़ा एसडीएम दुर्गा प्रसाद पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी कर दी।

बिलासपुर,25 अक्टूबर 2025। बिलासपुर में नगर निगम ने दिवाली पर्व के बाद एक बार फिर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार (25 अक्टूबर) को जवाली नाले के पास बनाए गए दुकान और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान लोगों ने निगम के अफसरों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया। वहीं,निगम के अफसरों ने कहा कि अभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों का अतिक्रमण हटया जा रहा है। बता दें कि यहां एक व्यापारी ने निना अनुमति के घर मांजला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया है,जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।



बिलासपुर में जवाली नाले पर चला बुलडोजर अवैध कमर्शियल बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं

बिलासपुर,25 अक्टूबर 2025। बिलासपुर में नगर निगम ने दिवाली पर्व के बाद एक बार फिर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार (25 अक्टूबर) को जवाली नाले के पास बनाए गए दुकान और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान लोगों ने निगम के अफसरों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया। वहीं,निगम के अफसरों ने कहा कि अभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों का अतिक्रमण हटया जा रहा है। बता दें कि यहां एक व्यापारी ने निना अनुमति के घर मांजला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया है,जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।

बिलासपुर में युवक पर हथौड़ी से हमला,गाड़ी में तोड़फोड़ करने से रोकने पर हुआ विवाद

बिलासपुर,25 अक्टूबर 2025। बिलासपुर में गाड़ी में तोड़फोड़ करने से मना करने पर युवक और उसके परिवार के लोगों ने मारपीट कर हथौड़ी से हमला कर दिया,जिससे एक युवक का सिर फट गया है। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। मंगला चौक स्थित मिनाचा कॉलोनी निवासी अजय विश्वकर्मा ने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के समय कुछ युवकों ने अजय की गाड़ी के शीट कवर पर ब्लेड मार दिया था। इसके बाद अजय ने उन युवकों पर नजर



रखना शुरू किया। इस दौरान पता चला कि पड़ोस का एक नाबालिग और उसके दोस्तों ने मिलकर गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। अजय के भाई ने मोहल्ले के एक युवक को गाड़ी के पहियों की हवा निकालते और तोड़फोड़ करते हुए पकड़ लिया। जब उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश की,तो युवक ने विवाद शुरू कर दिया।

बीजापुर में नक्सलियों ने मामा-भांजे को मार-डाला घर से बाहर बुलाकर धारदार हथियार से हत्या की,मृतकों में एक सीआरपीएफ जवान का भाई

बीजापुर,25 अक्टूबर 2025। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। नेलाकांकेर गांव में शुक्रवार (24 अक्टूबर) रात को नक्सलियों ने 2 युवकों को घर से बाहर बुलाया और मार डाला। दोनों रिश्ते में मामा-भांजे और पड़ोसी हैं। मामला उमूर थाना क्षेत्र का है। मृतकों की पहचान रवि कट्टम (25 वर्ष) और तिरुपति सोढ़ी (38 वर्ष) के रूप में हुई है। मृतक तिरुपति का भाई सीआरपीएफ में जवान है। पुलिस ने आशंका जताई है कि माओवादियों ने बदले की भावना से इस वारदात को अंजाम



दिया है। घटना की सूचना मिलते ही उमूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल,पुलिस और सुरक्षाबल आपसापस के क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं। यह घटना प्रदेश के गुहमंत्री विजय शर्मा के



बीजापुर और उमूर क्षेत्र के हालिया दौरे के कुछ दिनों बाद हुई है। माना जा रहा है कि माओवादी सुरक्षाबलों और प्रशासनिक गतिविधियों से बौखलाए हुए हैं। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के

मुताबिक,तिरुपति सोढ़ी 8वीं पास था। पेशे से किसान था। कट्टम रवि 12 वीं पास था। बताया जा रहा है दोनों का आवापल्ली,बीजापुर मुख्यालय आना जाना होता था। इसलिए मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने उन्हें मारा है। एक महीने में नक्सलियों ने 7 ग्रामीणों को मार डाला। जानकारी के मुताबिक,नक्सलियों ने अक्टूबर महीने में 5 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। गुहमंत्री अमित शाह के 4 अक्टूबर के बस्तर दौरे से ठीक पहले नक्सलियों ने सुकमा और बीजापुर जिलों में दो ग्रामीणों की हत्या की थी।